प्रक्रिया में करती हैं। विदेश जाने वाली दवाइयों की सही मात्रा की जांच, गुणवत्ता तय मानक के अनुसार होती है, पर देश के उपभोक्ताओं के लिए बनाई जाने वाली दवाइयां इस प्रक्रिया की बारीकी से महरूम रह जाती हैं।

देश में दवा कम्पनियों की जिस हिसाब से मशरूम ग्रोथ हो रही है और जगह-जगह पर छोटी-बड़ी कम्पनियां हैं, जिनमें तरह-तरह की दवाइयां बन रही हैं, इनमें तय मानक और सही दिशा में जांच-परख के लिए सरकारी तंत्र की कार्यकुशलता भी संतोषजनक नहीं है।

इन कम्पनियों में न तो सक्षम मानव संसाधन हैं और न ही उच्च कोटि और गुणवत्ता वाली मशीनरी। यहां तक कि ऐसी तथाकथित कम्पनियों में जिन सॉल्ट्स का प्रयोग होता है, वे निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करते। इनमें जीवन रक्षक दवाएं और सप्लीमेंट्री दवाइयां, जैसे-विटामिंस, एंटी ऑक्सिडेंट्स और दर्द निवारक लोशन एवं बाम आदि तमाम रूटीन की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयां गांवों, कस्बों और शहरों की आम दुकानों में उपलब्ध हैं। मरीजों को जब ऐसी सब-स्टैंडर्ड दवाएं मिलती हैं, तो निश्चय ही यह मरीजों के साथ छल है।

सरकार और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार में आने वाली सभी दवाएं तय मानक के अनुसार हों, जिससे जीवन-मरण से निजात पाने वाले संघर्षरत व्यक्ति को सही दवा मिले, ताकि वह सही मायने में स्वास्थ्य लाभ पा सके। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri P. Kannan, not present; Shri Y.S. Chowdary, not present.

Demand to impose import duty on the import of palm oil to protect the palm oil producers in andhra pradesh

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY (Andhra Pradesh): Sir, Andhra Pradesh is the leader in cultivation of oil palm with 1.3 lakh hectares' plantation out of the country's plantation of 2.10 lakh hectares. It all happened due to encouragement given by the Government of India through Technology Mission on Oilseeds and Pulses. Initially, oil palm farmers have been getting better remunerative prices.

Indonesia and Malaysia are leading producers of palm oil in the world. Last year, there was a bumper crop in these countries. Due to this, to increase exports, Malaysia took a decision that if per tonne raw palm oil cost comes down to 2250 Ringgits, export duty would become zero. And, last month, price has come down to 2147 Ringgits and Malaysia brought down export duty to zero. Looking at this, Indonesia has also brought down export duty to 8 per cent. Due to this, global palm oil prices have fallen drastically. This has resulted in large scale import of palm oil into the country resulting in drastic fall in palm oil price, thereby affecting

[Shri Palvai Govardhan Reddy]

the oil palm farmers. It is all happening due to reduction in the duty from 80 per cent in 2005 to zero per cent now. The total import of edible oils during 2011-12 has already reached 8.5 million tonnes.

Now, palm oil mills are purchasing one tonne Fresh Fruit Bunches for Rs.5,730. In May, it was Rs.7,800. The CACP recommended for giving Rs.8,500, but it has not been implemented. So, if free imports are allowed, oil palm farmers will be ruined. Hence, I request the Government of India to intervene in this immediately and impose import duty on palm oil and ensure implementation of CACP recommendation.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: I associate myself with the Special Mention made by Shri Palvai Govardhan Reddy.

Demand to withdraw the provision of making English Language a mandatory paper in Civil Services Examination held by UPSC

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (उत्तर प्रदेश) : महोदय, संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की परीक्षा के ढांचे में परिवर्तन करके अंग्रेजी जानने वाले छात्रों का दबदबा कायम करवा दिया है। इससे ग्रामीण इलाकों के पिछड़े एवं दलित आदिवासियों के छात्रों का नुकसान होगा, क्योंकि इनकी पढ़ाई-लिखाई अंग्रेजी वातावरण में नहीं होती। नये ढांचे में अंग्रेजी का पेपर अनिवार्य कर दिया है, जबकि पहले अंग्रेजी अथवा भारतीय भाषाओं का एक प्रश्न-पत्र होता था। पहले भाषा के पेपर में केवल पास होना अनिवार्य था, उसके नम्बर फाइनल की मैरिट में नहीं जुड़ते थे। सर, यह पूरे देश की क्लास वन परीक्षा का सवाल है। अब अंग्रेजी पेपर के नम्बर प्रिलिम्स एवं मेन परीक्षाओं के आधार पर तैयार की जाने वाली सूची का हिस्सा बनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिन छात्रों की अंग्रेजी कमजोर है, उनके लिए अब सिविल सर्विस की परीक्षा में चयनित होना आसान नहीं होगा। पुरानी पद्धति में क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर परीक्षा पास करने वाले छात्रों में देहात के गरीब, हर वर्ग के पिछड़े, दलित, आदिवासी छात्रों की संख्या अधिक थी। उदाहरण के लिए पिछले पांच वर्षों में गुजरात में 85 छात्रों ने सिविल सेवा परीक्षा पास की, उनमें से कम से कम 50 छात्रों ने गुजराती साहित्य की मुख्य पेपर बनाया। अब भारतीय भाषाओं जैसे - तमिल, तेलगु, कन्नड़, गुजराती, मलयाली, बंगला, असमी आदि भाषाओं को मुख्य पेपर में रखने की सुविधा नहीं होगी जबकि अंग्रेजी अनिवार्य होगी। इसका परिणाम यह होगा कि अभिजात्य वर्ग और आम आदमी के बच्चे के लिए यूपीएससी के चयन में भाषा एक दीवार बनकर खड़ी